



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 432]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/ आश्विन 7, 1905

No. 432]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का०आ० 695 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/83:—  
केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और  
नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश  
सं० का० आ० 319 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/76,  
तारीख 27 अप्रैल, 1976 द्वारा (जिसमें हममें हमके पश्चात  
उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स प्लाईवुड इंडस्ट्रीज  
लिमिटेड, पाम्पेर, जम्मू-काश्मीर नामक सम्पूर्ण औद्योगिक  
उपक्रम का प्रबंध 26 अप्रैल, 1981 तक की, जिसमें यह  
तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए  
ग्रहण करने के लिए जम्मू-काश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को  
प्राधिकृत किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि  
लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच  
वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी बना रहे,  
30 सितम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी  
सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए  
समय-समय पर निदेश जारी किए थे (देखिए भारत सरकार

833 GI/83

के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश  
सं० का० आ० 318 (अ)/18 कक उ० वि० वि० अ०/81,  
तारीख 25 अप्रैल, 1981 का आ० 287 (अ)/18कक  
उ० वि० वि० अ० 82, तारीख 26 अप्रैल, 1982 का० आ०  
763 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/82, तारीख 25  
अक्तूबर, 1982 और का०आ० सं० 233 (अ)/18कक/  
उ० वि० वि० अ०/83, तारीख 28 मार्च, 1983) ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकाहित में  
यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक की,  
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए  
प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और  
विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा  
18 क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा  
18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च,  
1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और  
अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[का० सं० 2(6)/81-सी यू एक्स]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

## ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 695(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 319 (E)/18AA/IDRA/76, dated the 27th April, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Jammu and Kashmir Industries Limited to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Plyboard Industries Limited, Pampore, Jammu and Kashmir, for a period of five years, that is, upto and inclusive of the 26th April, 1981 ;

And whereas, the Central Government being of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time for

such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1983 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. 318(E)/18AA/IDRA/81, dated the 25th April, 1981, S.O. 287(E)/18AA/IDRA/82, dated the 26th April, 1982, S.O. 763(E)/18AA/IDRA/82, dated the 25th October, 1982 and S.O. 233(E)/18AA/IDRA/83, dated the 28th March, 1983 ;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 2(6)/81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.